दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 06 जनवरी 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 99

महत्वपूर्ण एवं खास

जफर, दादापुरी को बिना सबूत गिरफ्तार किया जाना शर्मनाक है: चिदम्बरम

नयी दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि सदफ जफर, एस आर दारापुरी और पवन राव को हिंसा के मामले में उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाना ''शर्मनाक'' है। चिदंबरम ने कहा कि पुलिस ने चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति की है कि उनकी संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, ''सदफ जफर, एस आर दारापुरी और पवन राव आम्बेडकर को पुलिस की इस स्वीकारोक्ति के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया कि हिंसा में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। यह चौंका देने वाली स्वीकारोक्ति है।

कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 24 ट्रेनें लेट

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली आने वाली ट्रेनों का देरी से चलने का सिलसिला जारी है। आज रविवार को भी दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें दो से पांच घंटे तक लेट चल रही हैं। नई दिल्ली-फरक्का एक्सप्रेस 3.30 घण्टे, कटिहार-आनन्द विहार एक्सप्रेस 4.30 घण्टे, इलाहाबाद हमसफर एक्सप्रेस दो घण्टे, फरक्का एक्सप्रेस 3.30 घंटे, मुम्बई-अमृतसर-दादर एक्सप्रेस पांच घण्टे, हैदराबाद-निजामुद्दीन एक्सप्रेस पांच घण्टे, हैदराबाद-नई दिल्ली-तेलगांना एक्सप्रेस चार घण्टे ,मुम्बई-दिल्ली-दादर एक्सप्रेस पांच घण्टे देरी से दिल्ली आ रही हैं। पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस भी 4.45 घण्टे देरी से दिल्ली पहुंच रही है। रेलवे सुत्रों के मुताबिक, फिलहाल कोहरे और ठंड की वजह से ट्रेनों के परिचालन में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है।

अजित को वित्त और अनिल देशमुख को गृह विभाग

» उद्धव सरकार में विभाग बंटा

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शनिवार शाम को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव ठाकरे की तरफ से मंत्रालयों के बंटवारे की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई थी। जिसपर आज सुबह उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुश को गृह मंत्री बनाया गया है।

सीएए को लेकर सीतारमण का जन-जागरण अभियान

जयपुर (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीएए को लेकर जयपुर में जनजागरण अभियान में शिरकत कर रही है। जयपुर शहर में सांगानेर मण्डल के बूथ सख्या 189-190 पर पहुंच कर केंद्रीय मंत्री ने जन-जागरण अभियान का शुभारम्भ किया।

एक परिवार के 5 लोगों की हत्या, मृतकों में दो नाबालिग भी शामिल

प्रयागराज (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सोरांव थाना स्थित यूसुफपुर सेवाइत में शनिवार देर रात एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से हड़कंप मचा गया. सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गया है. पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में आपसी रंजिश में घटना को अंजाम देना सामने आया है, फिर भी कई बिंदुओं में जांच की जा रही है. मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मौके के लिए फारेंसिट टीम जांच में जुटी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार सोरांव थाना क्षेत्र के यूसुफपुर सेवाइत निवासी सोम दत्त तिवारी उनकी पत्नी व दो बच्चों व एक अन्य की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया।

सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में किया एक और केस दर्ज

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1993 और 2005 के बीच की समय के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में एक और केस दर्ज किया है।

एम एस निप्पन डेन्रो इस्पात लिमिटेड और कुछ अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने सभी आरोपियों नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व अन्य 11 पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश अप्रैल 2016 में दिया था। उस समय घूस लेने के लिए उकसाने के आरोप तय नहीं किए गए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 1999-2005 तक गलत तरीके से मिले चार कोयला ब्लॉकों के आवंटन की बात को छुपाया था। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध

करने वाले लोगों को ओबीसी और दलित विरोधी है घोषित कर दिया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान में उत्पीड़न के कारण वहां से आने वाले लोगों में अधिकतर शर्णार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलित वर्ग से हैं। उन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून लेकर आए हैं। नित्यानंद राय ने ओबीसी समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई सीएए का विरोध करता है तो उसे दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी घोषित कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीएए का विरोद ओबीसी समुदाय पर हमला है। मुट्ठी भर लोग बाहर निकल आए हैं और संशोधित कानून का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी लोगों को सिंह के समान गर्जना करनी चाहिए और प्रदर्शनकारियों से ज्यादा तेज आवाज उठानी चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने के लिए बधाई। हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया, सीएए लाए, पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वापस लाए। केवल एक ओबीसी ही ऐसा कर सकता था।

धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकताः पासवान, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भारतीय की नागरिकता को नहीं छीन सकती है। मंत्री ने नागरिकता संबंधित कदमों पर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए यह बात कही।

पीएम मोदी ने फिर की मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा

नयी दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की दो हफ्तों में तीसरी बार समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगले पांच साल के लिए अहम मंत्रालयों के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की कवायद के तहत यह किया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने शासन, प्रौद्योगिकी और संसाधनों जैसे विषयों पर शीर्ष नौकरशाहों की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि सचिवों की विभिन्न समितियों द्वारा दी गई प्रस्तुति पर बैठकों के दौरान मिले सुझावों के आधार पर सरकार अगले पांच साल के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप देगी। मंत्रालयों को कृषि, स्वास्थ्य, शासन और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि नीतियों को तेजी से और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। यह कार्य योजना शासन के लिए और कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से विकास करने के लिए नीतियों को लागू करने में और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस समीक्षा कार्य को पूरा करने के लिए आने वाले हफ्ते में मंत्रिपरिषद की और भी बैठक हो सकती है। हर महीने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आमतौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। लेकिन 21 दिसंबर 2019 से पिछले तीन मौकों पर बैठकें स्वतंत्र रूप से हुई।

देश से रोहिंग्या को बाहर निकालना होगा

» मोदी सरकार का अगला कदम

नयी दिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में हिंसा फैली हुई हैं। सरकार ने विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाया है कि हिंसा फैलाने में उनका हाथ है। विपक्ष ने लोगों को सीएए और एनआरसी को लेकर गुमराह किया हैं जिसके कारण हिंसा हुई। इसी बीच एक और कन्फ्यूजन बरकरार था कि क्या नागरिकता संशोधन कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा या नहीं? इस कन्फ्यूजन को खत्म करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। जितेंद्र सिंह ने सीएए को लेकर काफी बातें साफकर दी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या लोगों की ज्यादा आबादी हैं। रोहिंग्या लोगों की पहचान के लिए सूची बनाई जाएगी और अगर जरूरत होगी तो बायोमेट्रिक सर्टिफिक्रेट्स भी लिए जाएंगे क्योंकि सीएए रोहिंग्याओं को कोई लाभ नहीं देगा। ये उन तीन देशों से और छह अल्पसंख्यक समुदायों से नहीं आते हैं।ष् जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे किसी भी तरह से नागरिकता नहीं ले पाएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू-कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा और हम उनके निर्वासन को लेकर पूरी तैयारी करेंगे। जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जितेंद्र सिंह ने चिंता व्यक्त की कि आखिर रोहिंग्या बांग्लादेश से कश्मीर तक कैसे पहुंचे और रोहिंग्या को यहां पर बसाने के पीछे आखिर क्या मंशा थी। इसका पता विश्लेषकों और शोधकर्ताओं को लगाना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में कैसे आ गए। ऐसा क्यों किया गया. क्या उन्हें जम्मू में जम्मू की जनसांख्यिकी बदलने के मकसद से लाया गया था? इन सबकी जांच होनी चाहिए।

जीएफआर, ई-खरीद, जीईएम पर 3-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम संपन्न

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) और प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (आईएमपीएआरडी) के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के विचार विमर्श का आज समापन हुआ जिसमें तीसरे दिन वक्ताओं का फोकस सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर रहा।

केंद्र ने ई-सिगरेट रोकथाम कानून के तहत मामलों पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रोकथाम कानून के अनेक प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की संख्या, जब्त किये गये स्टॉक आदि पर सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।कानून पांच दिसंबर को अधिसूचित किया गया था जिसमें ई-सिगरेटों के उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री और विज्ञापन आदि पर रोकथाम के प्रावधान किये गये हैं और उल्लंघन करने पर जेल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर विभागों तथा संबंधित अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी निर्देश जारी करने तथा पुलिस एवं अन्य विभागों की सहभागिता के साथ महीने भर तक अभियान चलाने को कहा है। सरकार ने इस साल सितंबर में ई-सिगरेटों पर प्रतिबंध के लिए अध्यादेश जारी किया था। नये कानून ने इस अध्यादेश की जगह ली।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक अक्टूबर को ई-सिगरेटों पर पाबंदी को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए उस प्रावधान पर रोक लगा दी थी जिसमें स्टॉक को सरकारी परिसरों में जमा कराने की बात कही गयी थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ई-सिगरेट निर्माता और थोक विक्रेता अपने भंडार को अपने गोदाम में रख सकते हैं जहां कोई सरकारी अधिकारी उसकी जानकारी लेगा।

पाक उपदेश देने की जगह अल्पसंख्यकों को दें सुरक्षा: भारत

» पेशावर में सिख युवक की बेदर्दी से हत्या

नयी दिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर बेशर्मी और झूठ का पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान उलटे भारत को उपदेश दे रहे हैं। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के 48 घंटे के भीतर ही पेशावर में एक सिख युवक की हत्या हो गई। अब भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसे दूसरे देशों को उपदेश देने की जगह अपने यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

पेशावर में एक सिख युवक की हत्या मामले में भारत ने पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा कि वह दूसरे देशों को उपदेश देने की जगह अपने यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले पर जब पाकिस्तान घिरने लगा तो पीएम इमरान खान अपने दामन के दाग देखने की जगह भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगाने लगे। उधर, भारत ने कहा कि हम पेशावर में हुए जघन्य कृत्य की निंदा करते हैं और दोषियों को सजा देने की मांग करते हैं। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के मजह दो दिन बाद ही रविवार को एक सिख युवक की हत्या कर दी गई जिसके बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला एकबार फिर गरमा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाक से अपील की कि वह इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।

ननकाना साहिब हमले की स्पष्ट निंदा भी नहीं कर पाए इमरान

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के पेशावर में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के सदस्यों की श्निशाना बनाकरश् की जा रही हत्या की निंदा करता है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वह सच से भागना बंद करे और इस जघन्य कृत्य के दोषियों को दंडित करने के लिए कदम उठाए।

नुकसान पहुंचाया तो तबाह कर देंगे 52 ठिकाने

» ट्रंप की ईरान को चेतावनी

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, ईरान बदला लेने की धमकी दे रहा है। मैं ईरान को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उसने किसी अमेरिकी या अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया तो हमने ईरान के 52 ठिकानों की पहचान की है। ये 52 ईरानी ठिकानों में कई उच्च स्तर के हैं और ईरान और उसकी संस्कृति के लिए बेहद अहम हैं। इन ठिकानों पर बहुत तेजी से और बहुत विध्वंसक तरीके से निशाना बनाया जाएगा, इसलिए अमेरिका को और ज्यादा धमकी नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान कुछ अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाने के बारे में बात कर रहा है। वह अपने आतंकवादी नेता की हत्या का बदला लेने की बात कह रहा है जिसने अपने पूरे जीवन में अमेरिकी लोगों की हत्या की और कईयों को बुरी तरह घायल किया।

अमेरिका में सीएए के समर्थन में भारतीय समुदाय

» सिएटल-शिकागो में लगाए ये पोस्टर

वॉशिंगटन। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रदर्शन किया। वाशिंगटन के सिएटल शहर में लोगों ने सीएए के समर्थन में पोस्टर लेकर नारे लगाए। साथ ही इन लोगों ने इसे बेहद ही जरूरी कदम बताया।

लोगों के हाथों में पोस्टर थे और वे सीएए के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि सीएए सम्मिलित करने वाला है ना कि भेदभाव करने वाला, सीएए सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए हैं।

गौरतलब हो कि इससे पहले भी अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन जताने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किया था और सीएए को भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया। भारतीय-अमेरिकियों का एक समूह टाइम्स स्कॉयर पर एकत्र हुआ था। उनके हाथ में पोस्टर थे और वे सीएए और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन पोस्टरों पर लिखा था कि सीएए मानवाधिकारों के बारे में है, हम सम्मान के साथ जीने के अल्पसंख्यकों के अधिकार का समर्थन करते हैं, प्रवासी भारतीय सीएए का समर्थन करतें।

राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है मेगा पीटीएम, इसे रोकना गलतःकेजरीवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम) को रोकने की कोशिश किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि शिक्षा राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन किसी को शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

राउज एवेन्यू के एक स्कूल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वोट केवल उन्हें देना चाहिए जो अच्छी शिक्षा दिलाएं ना कि उन्हें जो धर्म के नाम पर लोगों के मन में भेदभाव पैदा करे। यह पूछे जाने पर कि भाजपा मेगा पीटीएम और उसके समय को लेकर आलोचना कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली ऐसी बैठक नहीं है। उन्होंने कहा, उन्हें (विपक्ष) यह राजनीतिक फायदे के लिए लगता है तो इस पर मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन यह गलत है। शिक्षा और स्कूल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, मेरा मानना है कि शिक्षा राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए, मगर शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि वे इसे रोकना क्यों चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपने स्कूलों में एक मेगा पीटीएम का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद जुलाई, 2016 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम शुरू की गई थी, जिसकी अभिभावकों ने तारीफ की है।

एनआरसी के लिए केंद्र सरकार ने नहीं की कोई पहलःराजनाथ

नयी दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर कोई पहल नहीं की है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह कवायद केवल असम में अंजाम दी जा रही है।

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में राजनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चुका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर कोई पहल नहीं की है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह कवायद केवल असम में अंजाम दी जा रही है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने संवाददाताओं से कहा एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चुका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आये राजनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों को यह संदेश देने का फैसला किया है कि वे सीएए के बारे में कोई भ्रम न पालें। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमें सर्वधर्म समभाव सिखाया है।